ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
कहां गयीं? रंग बिरंगी तितलियां

रविवारीय, 12 - 18 अप्रैल 2020 वर्ष- एक, अंक-36, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

मुख्यमंत्री ने बैशाखी की शुभकामनायें दीं

रांची :मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने देश एवं झारखण्डवासियों को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं व बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में समृद्धि लाए और कोरोना महामारी का विनाश करे। एक निवेदन, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रह कर बैसाखी मनाएं।

सहायता हेतु टॉल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क करें

रांची :राज्य स्तरीय कोरोना नियंत्रण केंद्र में कोविड -19 से संबंधित किसी भी तरह की सहायता हेतु टॉल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा सकता है। सहायता हेतु नियंत्रण केंद्र द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। यहां से खाद्य सामग्री, चिकित्सा, विधि व्यवस्था एवं झारखंड में फंसे मजदूरों से संबंधित मामले पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है । यहां से अब तक विधि व्यवस्था से संबंधित , चिकित्सा से संबंधित , झारखंड में फंसे व्यक्ति से संबंधित एवं अन्य शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

लॉकडाउन 2.0 तीन मई तक बढाया गया ◆ 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ छूट मिलेगी ◆ प्रधानमंत्री ने कहा

तीन मई तक अनुशासित रहें

हमने जो रास्ता चुना वो सही था:प्रधानमंत्री

13 अप्रैल को जब दस बजे प्रधानमंत्री टीवी चैनलों के माध्यम से देश की जनता को संबोधित कर रहे थे तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें तो दिख रहीं थी , पर कोरोना से निबटने का आत्मविश्वास भी दिख रहा था। उन्होंने बिना किसी संशय के कहा कि हमने बिल्कुल सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय लिया और आज भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में में अच्छी स्थिति में है।

प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम कोरोना से सफलतापूर्वक निबट रहे हैं और देशवासियों के त्याग और सादगी ने इसमें बहुत मदद की है और इसके लिये देश वासियों का आभार व्यक्त करना ये स्पष्ट कर गया कि प्रधानमंत्री किसी उहापोह में नहीं हैं उनके पास कोरोना महामारी से निबटने का संकल्प है।

कुछ क्षेत्रों में शर्तों के साथ छूट मिलेगी

21 दिनों के लॉकडाउन की सफलता को देखते हुये प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढा दिया है। लेकिन इस बार जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का केस कम होगा वहां शर्तों के साथ कुछ छूट दी जायेगी। रोज कमा कर जीवनयापन करने वालों की चिंता प्रधाममंत्री ने भी की और संभव है उनके लिये 20 अप्रैल से कुछ छूट मिले। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दे दिया कि देश लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती के लिये तैयार रहे।।

जानकारों का भी कहना है कि भारत ने समय पर देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया इसी कदम से वह अब तक भयावह संकट से बचा हुआ है। लेकिन अब किसी भी किस्म की लापरवाही भारत को सामाजिक संक्रमण की स्थिति में फंसा सकती है।

कहीं लोग भूख से व्याकुल कहीं दूध की बर्बादी

झारखंड में शहरों में लॉकडाउन की वजह से आदमी और जानवर तक भूख से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार और संस्थायें गरीबों को जैसे तैसे अनाज और भोजन दे रहे हैं वहीं गावों में किसानों के खेतों में तैयार सब्जी बर्बाद हो रही है। ढोने के साधन न होने और शहरों तक इसके न पहुंचने से गावों में इन सब्जियों को कोई पूछने वाला नहीं। कई जगह तो किसानों ने मवेशियों को ये सब्जी खिलानी शुरू कर दी ।

दुधारू पशुओं को खिलाने में चारे पर खर्च हो रहा है लेकिन दूध खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा। कुछ जगहों पर पशुपालकों ने कौड़ी के रेट पर दूध बेचा या सड़क पर दूध बहा दिया।

तकरीबन दस हजार कोराना पोजीटिव मरीज, हर रोज सात आठ सौ की बढती तादाद और हर दिन दर्जनों मौतों से हलकान भारत अभी कोरोना से भयंकर संघर्ष में उलझा हुआ दिख रहा है। इसके प्रसार का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि शुरूआत में जिस केरल में इसका असर सबसे ज्यादा था और जहां सबसे ज्यादा मरीज मिले थे वह केरल अब कोरोना संक्रमित राज्यों की सूची में एक से दस के बीच भी नहीं है। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में मरीजों की हजारो की संख्या और हर रोज बेकाबू होता यह आंकड़ा देश को डरा रहा है। तसल्ली की बात यही है कि भारत में अभी भी किसी विस्फोटक संक्रमण का रूप देखने को नही आया है । जैसा की अब तक अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन जैसे देशों मे हुआ है। भारत में कोरोना मरीजों की एक बड़ी तादाद अभी भी कुछ खास दर्जन भर शहरों से ही है। इस लिये बेहतर इंतजाम और रणनीति से इस पर काबू पाने की अच्छी संभावना है। वहीं इससे ज्यादा प्रभावित शहरों में भी एक खास मुहल्ले या पैकेट में इसके मरीजों के मिलने से आगे के संक्रमण पर काबू पाना संभव है।

इन सबके बीच बड़ी चिंता ये है कि डॉक्टरों, नर्सों जिन्हें हम कोरोना फाइटर कह रहे हैं खुद उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। कई दर्जन डॉक्टर और नर्स, चिकित्सकर्मी खुद इसके शिकार हो चुके है और कुछ की दुखद मौत भी हो चुकी है। भारत जैसे देश में जहां सरकारें और पूरा सिस्टम अपने कम साधनों के साथ इससे एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है वहीं वैसे तत्वों की भी कमी नहीं जो इस पूरे अभियान को ही पलीता लगा रहे हैं। अनुशासनहीनता, धार्मिक आयोजनों से कई जगहों पर लोग बाज नही आ रहे। कानून को ठेंगे पर रखने और और दुस्साहसी तत्वों की करतूत एक अलग ही समस्या बनी हुई है। इस कारण से देश सिर्फ वायरस, संक्रमण और मरीजों की रोकथाम से ही संघर्षरत नहीं है बल्कि पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को भी विधि व्यवस्था संभालने में पसीने छूट रहे हैं ।पंजाब में पुलिस पर हमला कर एक पुलिसकर्मी का हाथ ही काट डाला गया, मुहल्लों में पुलिस पर हमले जैसे वाकये कमोबेश सारे राज्यों में लॉकडाउन के दरम्यान पुलिस को विरोध और अपने ऊपर हमलों को भी झेलना पड़ा है।

किसानों पर दोहरी मार

लॉकडाउन के कारण देश में कृषि को बहुत नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। और फसलों की कटाई के लिये कुछ छूट देने की बात कही है। अभी खेतों में फसल पक चुके हैं, उनके कटाई को किसान बेचैन हैं। अगर अगले दो सप्ताह में इन तैयार खड़ी फसलों को काटा नहीं गया तो ये फसल बर्बाद हो जायेगी। दाने खेतों में ही बिखर जायेंगे। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन में भी कृषि कार्यों पर से पाबंदी हटा ली है और कृषि ये संबंधित दूकानों को खोलने का निर्देश है, पर तैयार फसलों को काटने के लिये मजदूरों की भारी कमी है। जो मजदूर फसल कटाई के मौसम में गावों की ओर लौटते थे वो अभी जहां तहां लॉकडाउन में फंसे हुये हैं। यानि एक तरफ जहां तैयार फसलों की कटाई के लिये मजदूर नहीं मिल रहे वहीं मजदूर जहां तहां फंस कर भूख और तंगी से जूझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने की उच्च-स्तरीय बैठक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये

झारखंड सरकार ने यह किया तय

◆ सभी जिलों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जिलों के दो वर्ग होंगे। ए वर्ग में वे जिले होंगे जहां 14 अप्रैल तक एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वर्ग बी में वह जिले होंगे जहां पॉजिटिव केस मिल चुके हैं या 14 अप्रैल तक और मिलने की आशंका है।

◆ए वर्ग वाले जिलों में कुछ रियायतें दी जाएंगी। बी वर्ग वाले जिलों में प्रतिबंध पूरी तरह से जारी रहेगा।

◆ जिलों में चिह्नित किए गए हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह का मूवमेंट पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यहां प्रशासन राशन और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था करेगा। 30 अप्रैल तक प्रदेश में कहीं भी पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और धारा 144 लागू रहेगा।

◆ 31 मई तक पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग की नीति भी इसी तारीख तक लागू रहेगी।

◆ वर्ग बी के जिलों की सीमाएं सील रहेंगी और सामान का परिवहन भी जिलों की सीमा के अंदर नहीं होगा। वर्ग ए के जिलों में जिलाधिकारी की अनुमति से परिवहन में रियायत दी जा सकती है। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच कोई आवागमन नहीं होगा।

वर्तमान में लागू पास मान्य होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण आदि जारी रहेगा।

◆ हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर जोखिम का आकलन कर डीएम निर्माण, औद्योगिक उत्पादन और खनन की अनुमति दे सकेंगे।

◆ स्टांप एवं रजिट्रेशन की सभी जिलों में नियमों के अधीन अनुमति।

ये भी हुआ तय

◆ ये सभी जगहें बंद रहेंगः होटल, धर्मशाला, होम स्टे, मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टूरेंट, बार, धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना किसी कार्मिक या अन्य व्यक्ति को हटाया नहीं जाएगा।

◆ हॉटस्पॉट को छोड़कर इनको रहेगी अनुमति : खेती किसानी, बागवानी, मौन पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कटाई बुवाई आदि को अनुमित रहेगी। राज्य की सीमा से बाहर और वर्ग बी वाले जिलों से श्रमिक नहीं लाए जा सकेंगे।

◆ 15 मई तक प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।

◆ अस्पतालों आदि को छोड़कर 15 मई तक प्रदेश मे एयर कंडीशनर के उपयोग पर भी रोक।

◆ रियायत : वर्ग ए वाले जिलों के बीच सात बजे से लेकर एक बजे के बीच खुद के वाहनों से यात्रा हो सकेगी। वर्ग ए और वर्ग बी वाले जिलों के बीच वाहन नहीं चलेंगे, केवल आवश्यक सामान की ढुलाई हो सकेगी।

◆ वर्ग ए वाले जिलों सहित अगर कहीं कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आते हैं तो प्रतिबंध अधिक सख्त किए जाएंगे।

◆ क्वारंटीन होने वालों को इधर-उधर आने-जाने की इजाजत नहीं होगी।

◆ सभी निजी अस्पताल और अन्य चिकित्सीय संस्थाएं प्रदेश में खुली रहेंगी और सोशल डिस्टेंस नीति का पालन होगा।

◆ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मनरेगा को वर्ग ए जिलों में अनुमति होगी।

ग्यारह सौ नेपाली मजदूर नहीं मना पायेगे नेपाली नववर्ष

एजेंसियां :विषुवत संक्राति 14 अप्रैल को है और उसी दिन नेपाल में नया साल मनाया जाना है। लॉकडाउन के चलते लोग पहले से ही घरों में हैं। लेकिन उनके 1100 से अधिक मजदूर भारतीय सीमा में ही 30 मार्च से क्वरांटाइन किए गए हैं। 30 मार्च को नेपाल ने अपने नागरिकों के लिए भी सीमा खोलने से मना कर दिया था। इसके बाद 7 अप्रैल, 2020 को अपना लॉकडाउन खत्म करने के बजाए बढ़ाते हुए उसकी अवधि 15 अप्रैल तक कर दी थी। भारत ने अपनी तरफ से इन नेपाली मजदूरों के लिए उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धारचुला सीमा पर तीन अलग-अलग स्थानों पर ठहराया गया है। धारचुला एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला ने कहा है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने नेपाल सरकार से सीमा खोलने के लिए बातचीत की थी लेकिन वह विफल रही। मजदूरों को यहां ही हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। काठमांडू से बातचीत विफल रही। नेपाली नागरिक अपने देश जाने के लिए परेशान हैं हालांकि उनकी सुविधा के लिए यहां हर इंतजाम किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अभी तक कोई भी नेपाली मजदूर में संक्रमण के लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं।

सालों से हरमू में बंद पड़े विद्युत शवदाहगृह को चालू करने की कवायद

आग लगने पर कुंआ खोद रहा है रांची नगर निगम

ग्रीन रिवोल्ट ने अगस्त 2019 अंक में ही इस पर विस्तृत खबर प्रकाशित की थी

संवाददाताः रांची हरमु में आज से दशक भर पहले विद्युत शवदाह गृह बनाया गया था। दलील दी गयी थी कि विद्युत शवदाह तकनीक से शवों को तुरंत जला दिया जायेगा। लेकिन यह पूरा निर्माण ही बेकार हो गया। अब सरकार फिर से इसे चालू करने की कवायद में जुट गयी है। देखना है इस बार ये चालू हो पाता है या फिर से सिर्फ ताम झाम ही होगा?

हैंडओवर मिलने के बाद नगर निगम की खुद इसका संचालन नही कर पाया। उसके बाद इसे निजी हाथों में देने का प्रयास हुआ लेकिन उस वक्त नगर निगम की उदासिनता और नियमों शर्तों के कारण जो लोग भी इसके लिये आगे आये थे उन्होंने भी अपने हाथ वापस खींच लिये। नतीजा ये हुआ कि दो करोड़ की लागत से बना विद्युत शवदाह गृह बिना चालू हुये ही जर्जर होकर बेकार हो गया है। आज इस परिसर में खटाल वालों का कब्जा है,हीटर ट्रांसफर्मर खराब हो चुका है।आज इसके चालू रहने से लॉकडाउन की घड़ी में शवों का दाह तुरंत हो जाता।

ये शवदाहगृह कहीं और बन रहा था न्लेकिन वहां विरोध होने पर इसे डमरू बाबा के आश्रम पर जबरन बनाया गया है। आस पास के लोगों का कहना है कि डमरूबाबा के श्राप के कारण ये शवदाहगृह कभी चालू हो ही नहीं सकता। देखना है लोगों की आस्था जीतती है या सरकारी प्रयास?

बीएयू छात्रों की उपलब्धि: बनाया डायबेटिक फ्रेंडली मल्टीग्रेन आटा

संवाददाता

- **कृषि स्नातक पाठ्यक्रम के अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के तहत छात्रों ने बनाया**
- **निर्मित आटे में 9 प्रकार के अनाज के दानों का उपयोग से**
- **विश्वविद्यालय में बिक्री के लिए उपलब्ध है दोनों प्रकार के आटे**
- **फायबर एवं पोषक तत्वों से भरपूर तथा मनुष्यों के पाचन तंत्र के अनुकूल**

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में अध्ययनरत कृषि स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के तहत डायबेटिक फ्रेंडली तथा मल्टीग्रेन आटा को बनाने में सफलता मिली है। दोनों प्रकार के आटे को छात्रों ने संकाय की गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्षा डॉ रेखा सिन्हा के मार्गदर्शन में कृषि छात्रों ने तैयार किया है।

मल्टीग्रेन आटा को बनाने में गेहूँ, मडुआ (रागी), मकई, सोयाबीन, बाजरा, चना, ज्वार एवं चौलाई (एमेरैनथश) के दानों का उपयोग किया गया है। प्रति 100 ग्राम इस आटे में 346।96 किलो कैलोरी उर्जा, 13।29 ग्राम प्रोटीन, 3।13 ग्राम, 66।50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2।57 ग्राम खनिज, 92।81 मि। ग्राम कैल्शियम तथा 4।96 मि। ग्राम आयरन की पोषक तत्व मौजूद बताया गया है। डायबेटिक फ्रेंडली आटा को बनाने में गेहूँ, मडुआ (रागी), सोयाबीन, जौ, बाजरा, जई तथा फेनुग्रीक के दाने का उपयोग किया गया है। प्रति 100 ग्राम आटे में 352।3 किलो कैलोरी उर्जा, 15।56 ग्राम प्रोटीन, 4।19 ग्राम वसा, 63।22 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2।58 ग्राम खनिज, 99।9 मि। ग्राम कैल्शियम, 5।42 मि। ग्राम आयरन तथा 122।8 मि। ग्राम सुपाच्य फाइबर के पोषक तत्व की मात्रा पाया गया है। इस आटे को 14 छात्र - छात्राओं के दल ने निर्मित किया है। इस दल में सत्यम, गौरव, कुंदन, प्रीति, ऋषिकेश, शिल्पी, दीपिका, अपूर्वा, अंकित, प्रेम, अजय, प्रिया, सन्नी, संगीता और भावना शामिल थे। छात्रों ने बताया कि आहार में गेहूं के स्थान पर मल्टीग्रेन आटा में शारीरिक फिटनेश और स्वस्थ रहने के लिए बेहतर पोषण मिलती है। इसे पाचन तंत्र के लिए बढ़िया पाया गया है। इसमें मौजूद फायबर एवं पोषक तत्व मनुष्यों के पाचन तंत्र के अनुकूल हैं। डायबेटिक फ्रेंडली आटा को मेथी, जई, रागी और सोयाबीन सहित गुणवत्ता वाले गेहूं और प्राकृतिक अनाज के मिश्रण से बनाया गया है। यह कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा है, जो प्री डायबेटिक और डायबेटिक व्यक्तियों के लिए काफी फायदेमंद है।

दल में शामिल छात्र सत्यम एवं शिल्पा ने बताया कि मधुमेह रोगियों के लिए गेहूँ के आटे के स्थान पर अधिक फाइबर एवं पोषण युक्त डायबेटिक फ्रेंडली आटा स्वस्थ विकल्प हैं। इससे मधुमेह रोगी के रक्त शर्करा के स्तर को अच्छी तरह प्रबंधित करने में मदद मिलती हैं। यह मधुमेह के लिए अनुकूल आदर्श आटा तैयार है। जिसके मिश्रित सामग्रियों में समृद्ध पौष्टिक प्रोफ़ाइल मौजूद है। जटिल कार्बोहाइड्रेट सामग्री के साथ आहार फाइबर में भी उच्च हैं। मल्टीग्रेन आटा ब्लड शुगर स्पाइक्स को नियंत्रित करने और वजन को प्रबंधित करने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। बाजार मांग को देखते हुए मल्टीग्रेन आटा एवं डायबेटिक फ्रेंडली आटा को बेहतर उद्यम के रूप में अपनाया जा सकता है। डॉ रेखा सिन्हा ने बताया कि गृह विज्ञान विभाग में मल्टीग्रेन आटा 80 रुपये प्रति किलो तथा डायबेटिक फ्रेंडली आटा 90 रुपये प्रति किलो की दर पर बिक्री हेतु उपलब्ध है।

डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव ने बताया कि आईसीएआर के निर्देश पर कृषि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्रों के लिए अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया है। इस कार्यक्रम से कार्यानुभव एवं प्रायोगिक ज्ञान हासिल होगा। छात्रों में उद्यमिता के गुर को सीखने और सफल उद्यमी बनने का लाभ मिलेगा।

पार्सल ट्रेन अब 25 अप्रैल तक चलेगी

रांची : 14/04/2020 तक 21 दिनों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु संपूर्ण देश में लॉक डाउन किया गया है ।लॉकडाउन के दौरान राँची रेल मंडल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मे कमी ना हो इसके लिए सतत प्रयासरत है एवं चौबीसों घंटे तत्परता के साथ कार्य कर रहा है इसी कड़ी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराने हेतु ट्रेन संख्या 00801/00802, शालीमार - रांची - शालीमार के बीच दिनांक 09.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक रोजाना विशेष पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया थाअब यह पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 25-04-2020 तक चलेगी ।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

कोरोना के बाद क्या?

कोविड -19 वायरस के संकट से तो दुनिया आज नहीं कल निकल ही आयेगी। मानव अपनी गलतियों का जितना खामियाजा भुगतना है वो भी भुगत लेगा। जितनी जानें जानी है वो अथक प्रयास के बाद भी चली जायेंगी। लेकिन इन सबके बाद एक और भयंकर संकट भी आसन्न होगी । वो है कोरोना की मार से आने वाली वैश्विक आर्थिक संकट। और उस संकट से पार पाने के लिये ये तय है कि दुनिया के सभी बड़े देश अंधाधुंध प्राकृतिक दोहन प्रारंभ करेंगे। चीन , अमेरिका, यूरोप, भारत कोई इसमें पीछे नहीं रहेगा। पहले भी विश्व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप एक दुसरे देशों पर लगाने का खेल चलते रहा है।

चीन ने बीजिंग महानगर के बीच में एक विशालकाय घूमता टावरनुमा एयर प्यूरिफायर लगा रखा है जो रात्रि में चला देने पर यहां की हवा को बिल्कुल साफ कर देता है। यानि विकसित और सक्षम देश तो खुद को बचा ही लेते हैं। अब जब कोरोना संकट से वैश्विक मंदी का खतरा है तो सभी देश संकट कोरोना से निबटने के बाद अपनी स्थिति सुधारने के लिये पर्यावरण की अनदेखी कर काम करेंगे?

क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी वैश्विक लॉकडाउन से विश्व पर्यावरण में हुये क्रांतिकारी सुधार और मानव जीवन के लिये संयोग से मिले इस संजीवनी का मोल आंक कर कुछ सार्थक कदम उठायेगा?

विकसित देश विकासशील देशों पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो ज्यादा कार्बन और प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं, अमेरिका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में ये आरोप लगाते रहा है कि अन्य देशों के प्रदूषण फैलाने के कृत्यों का नुकसान वह क्यों सहे? इसलिये वह किसी भी तरह की प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में कटौती नहीं करेगा। वहीं चीन को सिर्फ अपने व्यापार और धन अर्जित करने की भूख रही है उसे वैश्विक प्रदूषण और पर्यावरण के नुकसान की कभी कोई फिक्र नहीं रही , यूरोप का भी ऐसा ही कुछ रवैया रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी के काबू में आने के बाद सभी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये प्रदूषण और पर्यावरण के लिये नियमों को ताक पर रख कर ही काम करेंगे। और वह स्थिति पृथ्वी के लिये एक बड़ी संकट होगी। इन सबका सबसे ज्यादा खामियाजा छोटे विकासशील देशों को भुगतना पड़ेगा। यहां एक संकट ये भी है कि, प्रदूषण बढने और जलवायु परिवर्तन का नतीजा कोई जरूरी नहीं कि वही देश भुगते जिसने इसे बढावा दिया है, बल्कि यहां करे कोई भरे कोई वाली नौबत आ जाती है। अगर वैश्विक तापमान बढने से वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया या अफ्रिकी देशों में कोई संकट आता है तो ये जरूरी नहीं कि उसमें इन देशों की ही गलती हो। ये सब विश्व के विकसित और बड़े देशों का किया धरा भी हो सकता है। इन विषयों पर भी विश्व बिरादरी कोई मंथन करे इसकी उम्मीद तो फिलहाल कम ही दिखती है?

हाथ भी धोएं लेकिन पानी बर्बाद न हो

एन अर्जुन

कोरोना के कारण देश के सामने जलसंकट भी है। लोगों को दिन में कई बार हाथ धोने की सलाह दी जा रही है - कोरोना के वैश्विक महामारी के रूप में फैलने के बाद बार-बार लोगों को हाथ धोने के लिए जागरूक किया जा रहा है। 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए प्रेरित किया गया है। यह एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इससे पानी की भारी मात्रा में बर्बाद हो रही है, जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। भविष्य में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

जब से कोरोना का प्रकोप पूरे विश्व में फैला है, लोगों को दिन में कई बार हाथ धोने और घर वापस आते ही, नहाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना से बचने का यह एक बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही हम एक चीज भूल रहे हैं कि पूरी दुनिया पेय जल संकट से भी जूझ रही है। दुनिया भर के विद्वान यह अनुमान लगा रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। ऐसे हालात में लोगों को इस ओर ध्यान देना होगा कि हमारा देश भीषण जलसंकट से जूझ रहा है। 189 देशों में भारत 13वें पायदान पर खड़ा है और 'डे जीरो' की कगार पर 17 देश हैं।

आने वाला समय देश के लिए बहुत संकट भरा होगा, इसकी भयाभयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि 2030 तक हमारे देश के कई शहरों में पानी खत्म हो जाएगा, इसलिए समय आ गया है कि पानी की इस गंभीर समस्या को देखते हुए, मुश्किल हालातमें कोराना से भी लड़ना है और पानी भी बचाना है।

कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पानी यूं ही बर्बाद कर दें और फिर भविष्य में पानी के लिए तरसें। एक मुसीबत से छुटकारे के लिए किसी दूसरी मुसीबत को ना बुला लें, इसलिए हाथ तो धोएं, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि पानी भी बर्बाद नहीं हो। याद रखिए कि हम 'डे जीरो' की स्थिति तक पहुंच चुके हैं। यह भी ध्यान रखें कि आगे आने वाले महीने गर्मियों के हैं, जिसमें पानी की किल्लत और बढ़ने वाली है।

करोड़ों लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर उठेंगे...

जल संकट से जूझते लोग। भारत में यह बड़ी समस्या बन रहा है। - फोटो : अमर उजाला

कोरोना से बचाव का सबसे आसान तरीका यह बताया जा रहा है कि दिन में कई बार हाथ को साबुन से करीब 20 सेकंड तक रगड़-रगड़ कर धोएं और हो सके तो बाहर से आने के बाद तुरंत ही नहा लेना चाहिए। यह बहुत ही बेहतर तरीका है, कोरोना से बचने का, लेकिन अक्सर जब हाथ धोने के लिए नल खोल लेते हैं, उसके बाद उसे बंद करना भूल जाते हैं और क्योंकि सारा का सारा ध्यान हाथ रगड़ने और जैसे बताया गया है, उसी तरह से रगड़ने में चला जाता है।जब तक होश संभालते हैं, तब तक काफी सारा पानी बह चुका होता है। इस तरह से रोजाना भारत में लाखों गैलन पानी नालियों में बह रहा है। लोग लॉक डाउन के दौरान ज्यादा पानी का उपयोग कर रहे हैं।

देश के कई शहर आज भी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और कई शहरों में संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नीति आयोग अपनी रिपोर्ट में पहले ही गंभीर जल संकट की ओर इशारा कर चुका है। आयोग ने कहा था, 2020 से यह समस्या शुरू हो जाएगी और 2030 तक कई शहर पानी के तरसेंगे, जिनमें सबसे ज्यादा दिल्ली, बंगलूरू, चेन्नई और हैदराबाद के लोग शामिल होंगे। देश में नदियां, झील, जंगल, जल निकाय आदि सूखने के कगार पर हैं या पूरी तरह से सूख जाएंगे। अगर हालात नहीं सुधरे तो 2030 तक देश के करीब 40 फीसदी लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा। यह केवल भारत की स्थिति ही नहीं बल्कि कतर, इजरायल, लेबनॉन, ईरान, जार्डन, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरब, एरिट्रिया, यूएई, सैन मैरिनो, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्केमिस्तान, ओमान और बोत्सवाना जैसे देशों में भी यही समस्या है। इन सभी देशों में पानी का संकट अत्यंत ही गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है। यानी करोड़ों लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर उठेंगे।

क्या है डे जीरो?

आईसीएमआर के ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों में 83 फीसदी पुरुष हैं। कुछ समय पहले एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत 'डे जीरो' के कगार पर खड़ा है। यह एक बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर हम इसमें प्रवेश कर जाते हैं, तो सोचिए क्या होगा। रिपोर्ट कहता है कि भारत भीषण जल संकट से जूझ रहा है, और यह डे जीरो के बहुत करीब खड़ा है। डे जीरो का मतलब होता है, जब नलों तक में पानी सूख जाता है। नलों में पानी सूखने मतलब है, देश के करोड़ों लोग पानी के लिए तरसेंगे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लोगों को बाढ़ और सूखे की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2002 में देश की महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने के लिए एक वृहद योजना बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की 60 नदियों को जोड़ने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी। क्या पीएम देश की जनता को जल संकट से उबार पाएंगे।

उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जल्द ही हम इस योजना को मूर्त रूप लेते देख पाएंगे और भविष्य में बाढ़ एवं सूखे की समस्या पर प्रभावी रूप से नियंत्रण कर लिए जाएगा और देश जल संकट की समस्या से सदा के लिए निजात पा लेगा। अक्सर हम देखते हैं कि मानसून और उसके बाद बरसने वाला पानी, नदियों और नालों के माध्यम से बह कर समुद्र में गिर जाता है और सारा पानी बेकार हो जाता है। हमें समय रहते जागना होगा और बारिश के पानी के संरक्षण पर जोर देना होगा ताकि बेकार जाने वाले पानी को बचाकर, भू-जल पर हम निर्भर कम हों।

इसी तरह से कोरोना के वैश्विक महामारी के लिए हाथ धोना और नहाना जरूरी है। बस, इतना ध्यान रखें कि नलों में पानी व्यर्थ नहीं बहे। क्योंकि कहते हैं ना, जल है तो कल है।

पर्यावरण के लिये हर साल छुट्टी की ठोस योजना बने

अतुल सिंघल

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को आदेश दिया है कि लॉक-डॉउन के दौरान यमुना नदी के पानी के साफ होने पर रिपोर्ट पेश करे। दरअसल सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि लॉक-डॉउन की अवधि के दौरान यमुना का पानी बिलकुल साफ नजर आ रहा है। माना रहा है कि लॉक-डॉउन की वजह से दिल्ली एनसीआर में यमुना के किनारे बने शहरों के कल-कारखानों के बाद होने से उनका कचरा और गंदा पानी यमुना में नहीं जा रहा लिहाजा यमुना का जल साफ दिखाई दे रहा है।

दरअसल,लॉक-डॉउन के सहारे प्रकृति ने सारी दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। अगर इस संदेश को समझे तो पाएंगे कि दुनिया के अधिकांश शहरों में सांस तोड़तीहवा साफ हुई है। हर समय धुएं से काला रहने वाला दिल्ली जैसे महानगरों का आसमान नीला दिखाई देने लगा है और रात को तारे चमकने लगे हैं।

चार दशक के बाद जालंधर से हिमालय की बर्फीली चोटियों के दृश्य ने रोमांचित कर दिया। दिल्ली में हर रोज 11 लाख गाड़ियां दूसरे शहरों से आती है जो लॉक-डॉउन के बाद राजधानी में नहीं घुस पाईं। लिहाजा दिल्ली की दमघोटूं हवा साफ नजर आने लगी। यहां तक की राजधानी के प्रमुख चौराहों पर भी वायु प्रदूषण नाम की कोई चीज नहीं बची। जबकि शहरों की सड़कों पर जंगली जानवर नजर आने लगे।

दिल्ली से सटे नोएडा के सबसे व्यस्त समझे जाने वाले मॉल जीआईपी के सामने नील गायें और हिरण घूमते देखे गए। ओखला पक्षी विहार में पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा और एनसीआर के शहरों के पॉर्कों से गायब तोते और दूसरी चिड़ियों की आमद शुरू हो गई। हरिद्वार से आए एक वीडियो में बताया गया कि राजाजी नेशनल पार्क से आया हाथी हर की पौड़ी के नजदीक गंगा में स्नान कर रहा है। गंगा भी बिल्कुल निर्मल हो गई हैं।

दक्षिण के किसी समुद्री तट पर एक हिरन अटखेलियां करता नजर आया।लॉक डाउन के कारण मृत्यु दर में भी खासी कमी आई है। राजधानी के सबसे बड़े, व्यस्त और व्यवस्थित समझे जाने वाले अंतिम संस्कार स्थल निगम बोध घाट पर भी इन दिनोंआम दिनों से 25 फीसदी कम शव ही अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं।लॉकडाउन के दौरान इन लोधी रोड, पंजाबी बाग स्थित शमशानघाटों पर भी अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों में भी 25 से 50 प्रतिशत तक की कमी आई है। अगर इसका सही से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु समाप्त प्रायः हो गईं। प्रदूषण के चलते सांस के मरीजों को दिल्ली में नया जीवन मिला है और तनाव कम होने से हृदयाघात भी घटे हैं। यही नही अपराधों में भी बेतहाशा कमी आई है। लोग एकाकी से संयुक्त परिवार की तरफ लौटेंगे। परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताना एक अनूठा अनुभव साबित हुआ है। स्लम बन चुके महानगरों से प्रवासी लोगों का अपने गांवों की तरफ लौटना भी एक ग्रास बनाना शुरू कर दिया है। जिसका परिणाम सारा विश्व भोग रहा है। भौतिकतावादियों का तर्क है कि किसी बीमारी या महामारी की वजह से सारी दुनिया को घरों में कैद नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक कोरोना के इलाज का जवाब यह भौतिकतावादी नहीं खोज पाए।

दूसरी तरफ दुनियाभर के पर्यावरणविद और प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि जिस तरह से लॉक-डॉउन के बाद सारी दुनिया में सकारात्मक प्रभाव देखे गए। उससे यह अनुभव सामने आया कि ठोस नीति बनाकर स्वेच्छा से अलग-अलग शहरों में साल में एक बार लॉक-डॉउन करके प्रकृति के संतुलन को साधा जा सकता है। इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में व्रत रखने का महत्व है। वैज्ञानिक दृष्टि से व्रत के दौरान हमारा शरीर स्वयं का शोधन करता है। जिससे शरीर की कई बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार साल में 15 दिनों के लिए लॉक डाउन करके प्रकृति को अपनी पुरानी रंगत में लौटने का अवसर मिल जाएगा।

आज हाथ मिलाने, शवों के दाह संस्कार, शाकाहार अपनाने जैसे भारतीय सनातन परंपरा की तारीफ अमेरिका, स्पेन, इटली, जापान, कोरिया और जर्मनी के लोग भी कर रहे हैं और इसे अपनाने की वकालत भी रहे है।

किसान की मुश्किल

किसान खेती पर मौसम की मार के अभ्यस्त हैं। पर तैयार फसल की कटाई, मंड़ाई न हो पाए, उसे मंडी तक न पहुंचाया जा सके, तो वह दर्द असह्य हो जाता है। इस वक्त बहुत सारे मजदूर जो शहरों में दिहाड़ी करते थे या मनरेगा वगैरह में काम करते थे, वे गांवों में खाली बैठे हैं।

खेती में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर एक से दूसरे प्रदेशों में आवाजाही करते हैं।पूर्ण बंदी के इस माहौल में कल-कारखाने, दुकानें, व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, तो किसानों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। कोरोना विषाणु का प्रकोप ऐसे समय में हुआ जब गन्ने, आलू, प्याज, दलहन वगैरह की फसलें खेतों में तैयार थीं और गेहूं की फसल तैयार हो रही थी। चीनी मिलें पेराई अवधि समाप्त होने से पहले ही बंद हो गईं, जिस-के चलते गन्ने की बहुत सारी फसल अभी खेतों में खड़ी है। इससे गन्ना किसानों की परेशानियां समझी जा सकती हैं। अब गेहूं की फसल पक कर तैयार है, पर कटाई के लिए न तो पर्याप्त मजदूर मिल पा रहे हैं और न मशीनें। सामाजिक दूरी बना कर रहने और पांच से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा न होने का नियम है, सो जहां स्थानीय मजदूर उपलब्ध हैं, वहां भी कटाई में मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस साल मौसम का मिजाज भी बदलता देखा जा रहा है। बारिश की वजह से पहले ही फसलों को काफी नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में गेहूं की कटाई, मंड़ाई और फिर बाजार तक पहुंचाना किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए किसान संगठनों की ओर से मांग उठ रही है कि सरकार इस मामले में ढिलाई बरते, किसी योजना से इन्हें मदद व राहत दे।

बटाईदार और ठेकेदार भी क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे गेहूं

एजेंसियां : उत्तर प्रदेश में बटाई और ठेके पर खेती करने वाले किसान भी क्रय केंद्रों पर अपना गेहूं बेच सकेंगे। बटाईदार को किसान का सहमति पत्र और ठेकेदार को लेखपाल की संस्तुति के बाद ही क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने का अधिकार मिलेगा। इस बार गेहूं खरीद की राशि किसान, बटाईदारों और ठेकेदारों के खाते में आरटीजीएस से नहीं बल्कि पीएफएमएस से पहुंचेगी।

जिले में गेहूं खरीद के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 57 क्रय केंद्रों का अनुमोदन किया जा चुका है। कोरोना वायरस के चलते एक अप्रैल से होने वाली गेहूं खरीद को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन सरकार ने बटाई और ठेके पर गेहूं की बुवाई करने वालों को भी गेहूं क्रय करने का अधिकार दिया है। इसके लिए बटाईदार और ठेकेदार को किसान और लेखपाल से संस्तुति करानी होगी। इसके साथ ही बटाईदार और ठेकेदार को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।

नियमों के मुताबिक ठेके पर जमीन लेने वाले को रजिस्ट्रार के यहां भी अनुबंध कराना होगा। नियम यह भी है कि यदि कोई किसान 100 क्विंटल से अधिक गेहूं बेचता है, तो उसे एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि गेहूं खरीद के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। 15 अप्रैल से गेहूं खरीद की जाएगी। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1940 रुपये है।

लंबा लॉकडाउन भारत के लिये हितकर नहीं

कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में लॉकडाउन चीन, अमेरिका और बड़े यूरोपीय देशों में स्वैच्छिक हथियार बना। दिलचस्प है कि जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने लॉकडाउन को नहीं अपनाया जबकि वहां इस महामारी से होने वाली मृत्यु दर सबसे कम है। इन देशों और भारत के बीच कम से कम चार बड़े अंतर हैं जो भारत के लिए लंबे लॉकडाउन को वांछित नहीं बनाती। पहली बात तो यह कि भारत एक गरीब मुल्क है जहां औसत आय चीन की औसत आय के पांचवें हिस्से और यूरोप या अमेरिका की औसत आय के 20वें हिस्से के बराबर है। देश के 20 फीसदी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। जबकि 20 से 30 प्रतिशत लोगों की हालत उनसे कुछ ही बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि करीब आधी आबादी किसी तरह दिन काट रही है। मौजूदा लॉकडाउन जैसी स्थिति में उनके पास आय में आई कमी से निपटने का कोई जरिया नहीं है। लॉकडाउन बढने पर वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाएंगे।

कोरोनावायरस महामारी के बीच निजता का प्रश्न

देवांशु दत्ता

कोरोनावायरस महामारी के बीच सूचना तकनीक तथा कृत्रिम मेधा (एआई) का कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने प्रभावित लोगों की पहचान करने, क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी करने, अहम स्थानों की खोज करने और बड़े स्तर पर डेटा विश्लेषण करने के उद्देश्यों से एआई एल्गोरिद्म तैयार किए हैं। लोगों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए कई देशों की सरकारों ने कई ऐप जारी किए हैं। कारोबारी स्तर पर घर से काम करने की आवश्यकता के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का चलन बढ़ रहा है। कई लोग दोस्तों से बात करने के लिए भी इससे संबंधित ऐप का उपयोग कर रहे हैं।

हालांकि निजता तथा सुरक्षा से जुड़े कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपयोग से जुड़े लाभ, हानि जैसे अहम सवाल एक लंबे वाद-संवाद का हिस्सा हैं। हमें यह समझना होगा कि आखिर हमारी जरूरतें क्या हैं? इसलिए जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात आती है तो आपको अपनी जरूरतें परिभाषित करनी चाहिए। इसके बाद इंटरनेट पर विभिन्न समीक्षाओं को पढने एवं विश्लेषण करने के बाद ही किसी ऐप का चयन करना चाहिए।

अगर आपको केवल दूरदराज बैठे अपने घर-परिवार वालों या दोस्तों के साथ बातचीत करनी है तो आपको ऐसे ऐप की जरूरत नहीं है जो 250 लोगों को एक साथ वीडियो कॉलिंग की सुविधा देता हो। आपको वह बातचीत रिकॉर्ड भी नहीं करनी है। हालांकि कर्मचारियों तथा ग्राहकों से बातचीत करने वाले कारोबारियों को ऐसी कुछ खासियतों की जरूरत होगी जिसमें छोटी-बड़ी डिजिटल फाइलें भेजने के विकल्प भी शामिल हों। प्रत्येक उपयोगकर्ता गोपनीयता तथा निजता चाहता है। सुरक्षा का पहला स्तर तो ऐप ही है जिसमें हैक होने जैसी खामियां नहीं होनी चाहिए। अधिकांश ऐप आपको मोबाइल फोन के स्टोरेज, माइक, कैमरा और कई तरह के बदलाव करने जैसी अनुमति ले लेते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर प्रदाताओं को डेटा चोरी नहीं होने से जुड़ी प्रतिबद्धताएं देनी चाहिए। डेटा को किसी सुरक्षित सर्वर पर रखना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रदाता को उपयोगकर्ताओं से जुड़ा डेटा नहीं बेचने से संबंधित अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट करनी चाहिए। उदाहरण के लिए जूम एक लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता है और फेसबुक को ग्राहक संबंधी डेटा बेचने के आरोप में इस पर कार्रवाई की गई है।

जब सरकार द्वारा जारी किए गए प्लेटफॉर्म की बात आती है तो कई दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं। कई बार उपयोगकर्ताओं के पास विकल्प नहीं होते और उन्हें संबंधित ऐप इंस्टॉल करने के लिए मजबूर किया जाता है। वास्तव में जो ऐप आपकी लॉन्टेक्स सूची साझा कर रहा है, वह एक निगरानी ऐप है। ये ऐप उपयोगकर्ताओं की स्थिति तथा डेटा को ट्रैक करते हैं। चिकित्सा संबंधी आंकड़ों जैसे कई अहम डेटा का प्रसंस्करण करके उन्हें कई तरह से एक जगह सहेज लिया जाता है। इन ऐप के लिए ब्लूटूथ तथा जीपीएस को ऑन करना भी जरूरी होता है जिससे गोपनीयता तथा सुरक्षा संबंधी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं तथा हैकिंग की संभावना बढ़ जाती है।

'इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट' जैसे कुछ ऐप अपराधियों की निगरानी के लिए बनाए गए हैं। ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद वस्तुविशेष की स्थिति, दिशा, यात्रा की गति, दिन विशेष की रियल टाइम गतिविधियों आदि पर नजर रखी जा सकती है। इन आंकड़ों को रियल टाइम में डाउनलोड किया जा सकता है जिस-का बाद में विश्लेषण किया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा जारी ऐप आरोग्य सेतु के लिए चौबीसों घंटे स्थिति तथा ब्लूटूथ को ऑन रखना जरूरी है। ब्लूटूथ के जरिये संबंधित फोन ब्लूटूथ की रेंज में किसी दूसरे फोन को खोजता है। संक्रमण से ग्रसित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई डिवाइस को लैग कर दिया जाता है और ब्लूटूथ के जरिये ऐसी किसी लैग की हुई डिवाइस की खोज की जाती है। इसके अलावा, फोन पर स्थिति ऑन रहती है जिससे संबंधित व्यक्ति या फोन जिस जगहों पर गया हो, उन्हें रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाए। सिंगापुर, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इजराइल आदि इसी तरह के ऐप जारी कर रहे हैं। हालांकि सिंगापुर द्वारा जारी ऐप ओपन सोर्स ऐप है अर्थात इसमें अगर कोई सुरक्षात्मक खामी है तो इसे बहुत जल्दी ढूंढा जा सकता है। जर्मनी, इटली तथा फ्रांस के नागरिक निजता तथा सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित नहीं हैं क्योंकि इस देशों ने यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटक्शन रेग्युलेशन (जीडीपीआर) के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। जीडीपीआर के तहत नागरिकों से पूछा जाता है कि उनसे संबंधित कौन-सा डेटा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। इससे भी अहम बात यह है कि नागरिकों के पास 'राइट टू फॉर्गेट' का अधिकार है अर्थात, व्यक्ति अपने किसी भी डेटा को रिकॉर्ड से हटाने के लिए कह सकता है। संबधित डेटा का दुरुपयोग करने पर जुर्माना और दूसरे तरह के दंड का भी प्रावधान है। हालांकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोग्य-सेतु ऐप ओपन सोर्स ऐप नहीं है जिसका अर्थ है कि अगर इसमें कोई खामी मिल जाती है तो हैकर इसका उपयोग कर सकता है। साथ ही, भारत में निजी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। हालांकि इससे जुड़ा एक कानून प्रस्तावित है, लेकिन इस मसौदा विधेयक में भी सरकार के पास किसी भी तरह के डेटा को संजोने की शक्ति होगी।

अगर आपको आरोग्य-सेतु ऐप का उपयोग करना है तो इसे इंस्टॉल करने से पहले अपने निजी डेटा को स्मार्टफोन से हटा दें और इसे फैक्टरी रीसेट कर लें। बाद में जब आप इसे फोन से हटाएं तो भी सबसे पहले फैक्टरी रीसेट कीजिए और इसके बाद ही फोन का इस्तेमाल करें। जिस समय ऐप फोन में मौजूद है, किसी भी तरह के निजी डेटा को फोन में रखने से बचें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, निजता का ध्यान रखें।

राकेश सिंह ने अबतक 800 जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में पहुंचाया राशन

रांची :विद्यानगर महिला समिति के तत्वाधान में रविवार को समाजसेवी राकेश कुमार सिंह ने कोविड़ 19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 40 जरूरतमदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया। उन्होंने बताया कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले लोग इस कोरोना की चपेट में ना आ जाए उसे देखते हुए उन्होंने सभी दिहाड़ी मजदूरों के घर पर जाकर राशन पहुंचाया है। राकेश ने बताया कि अब तक लगभग 800 लोगों तक राशन सामग्री दिया जा चुका है। लगातर आगे भी जरूरतमंद लोगों के बीच राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोविड 19 कोरोना से बचने के उपाय बताएं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोरोना के दौरान एक भी व्यक्ति भूख से ना मरे इसपर फोकस कर राशन वितरण किया जा रहा है। मौके पर मनोज कुमार राय, मुकेश सिंह राजपूत, सुधीर शर्मा, वरुण झा, संजय गुप्ता उर्फ गांधी का अहम योगदान रहा है।

रांचीः अग्रवाल सभा के द्वारा 800 फूड पैकेट का वितरण किया गया एवं आज तक कुल करीब 11250 फुड पैकेट का वितरण किया जा चुका है

अग्रवाल सभा फूड पैकेट का निर्माण और वितरण कर रहा है

रांची : कोरोना संकट में जरूरतमंदो के लिये अग्रवाल सभा भोजन बनवा कर वितरित रहा है । अध्यक्ष पवन पोद्दार ने बताया कि पूरी सुरक्षा के साथ खाना बनवाया जा रहा है एवं पैकिंग की व्यवस्था की जा रही है पैकिंग करने वाले हमारे सभा के सेवादार पुरे सोशल डिस्टेंस को पालन कर रहे हैं, हाथों में ग्लब्स पहनते हैं। हाथों को सैनिटाइज करते हैं जिससे किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। आज का फूड पैकेट समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं सभा के पूर्व अध्यक्ष परिवार श्री बृजमोहन जी भागचंद पोद्दार परिवार ने स्वर्गीय सरिता देवी पोद्दार की स्मृति में मुहैया कराई गई है इसके लिए सभा मंत्री कौशल राजगढ़िया ने दाता के समस्त सदस्यो की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, सभा की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया। संयोजक विनोद कुमार जैन ने बताया कि हमारी संस्था के द्वारा जितने भी फूड पैकेट वितरण किए जा रहे हैं वे सभी प्रशासन एवं सभा सदस्यों की देखरेख में वितरित हो रहे हैं, तथा उस पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह का अनाज का दुरुपयोग ना हो। साथ ही उन्होंने बताया कि समाज बंधुओं का हमें निरंतर सहयोग मिल रहा है जिसके कारण हम सभी मिलकर बड़ी सुगमता के साथ फूड पैकेट तैयार कर रहे हैं।

इस कार्य में पवन पोद्दार, कौशल राजगढ़िया, विनोद जैन,रतन मोर सुनील पोद्दार,अनिल अग्रवाल,नीपू मोदी,हनुमान बेडिया,कपिल पोद्दार,प्रकाश पोद्दार, संजय पाण्डे,रामा शंकर बगडिया, सहित भवन के कई सदस्य एवं सेवादारीगण सेवा प्रदान कर रहे हैं।

लॉकडाउन में नुकसान से बचने के लिए क्या करें किसान?

एजेंसियां

ICAR ने दिए सुझाव

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने लॉकडाउन से कृषि उत्पादों को नष्ट होने से किसानों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए सलाह दी है। आईसीएआर ने कहा है कि वाइन, टमाटर प्यूरी और मूल्य वर्धित उत्पाद बनाए जाने चाहिए।

देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन में पाबंदियों के मद्देनजर आईसीएआर ने कृषि क्षेत्र के लिए राज्यवार दिशा निर्देश जारी किए हैं औक कहा है कि किसानों को जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बचाना चाहिए। इसमें किसानों से वाइन, जैम, जेली, स्कवैश, टमाटर प्यूरी और मशरूम के मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने का सुझाव दिए गए हैं।

मेघालय के किसानों के लिए दिशानिर्देश आईसीएआर ने मेघालय के किसानों को दिशानिर्देश दिए, जिसमें कहा गया कि स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाले किसान इसके बिकने में परेशानी होने पर इससे वैल्यू एडेड उत्पाद बनाए। किसान स्ट्रॉबेरी से वाइन, जैम, जेली और स्कवैश बना सकते हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान नहीं होगा। मालूम हो कि मेघालय में किसानों को मक्का के बीज और कुछ उ-वर्रक घर पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं त्रिपुरा के किसानों को टमाटर की बिक्री में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें टमाटर को जीरो एनर्जी कोल्ड चेंबर में भंडारण करने या टमाटर की प्यूरी बनाने का सुझाव दिया गया है। इतना ही नहीं, त्रिपुरा राज्य में मछली पालन करने वाले किसानों को घर में सरसों खल, चावल और पके हुए चावल से मछली चारा बनाने को कहा गया है। नागालैंड की बात करें, तो आईसीएआर ने नागालैंड में मशरूम के तैयार होने और उसकी बिक्री नहीं होने पर उसे धूप में सूखने की सलाह दी है। अगर ऐसा ना हो पाए, तो चूल्हे पर भी इसे सुखाया जा सकता है, जिसमें नमी की मात्रा पांच से छह फीसदी से अधिक नहीं हो।

इन उत्पादों का करें भंडारण

असम में आलू, टमाटर और मिर्च की बिक्री नहीं होने की स्थिति में उसे कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बांस से बने ह-वादार संरचना में आलू का भंडारण करने को कहा गया है।

अनाज कैसे बेचेंगे? हरियाणा के किसानों के माथे पर उभरी चिंता की लकीर

एजेंसियां :हर साल एक अप्रैल से हरियाणा की मंडियों में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार देश में लॉक डाउन घोषित होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। प्रदेश सरकार ने गेहूं की खरीद 20 अप्रैल और सरसों व चना को 15 अप्रैल से खरीदने का ऐलान किया है। लॉक डाउन के बीच बार-बार मुख-यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किसानों को भरोसा दिला रहे है कि उनका एक-एक दाना सरकार खरीदेगी, लेकिन मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जेपी दलाल की बातों पर किसान भरोसा नहीं कर पा रहे है। हरियाणा सरकार द्वारा रबी की फसल खरीदने के लिए लगाई गई कुछ शर्तों ने किसानों की माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है।

हरियाणा में अबकी बार करीब 25 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल है और इससे करीब 125 से 130 लाख टन गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद है। कुल गेहूं उत्पादन में से करीब 80 फीसदी गेहूं की खरीद की जाती है। पिछले साल चार खरीद एजेंसियों (हैफेड, डीएचएफसी, हैफेड और हरियाणा वेयर कॉरपोरेशन) के जरिये 93,20,866 मिट्रिक टन गेहूं खरीदा था। इस बार पांच लाख 62 हजार 440 हेक्टेयर रकबे पर सरसों और 45 हजार 500 हेक्टेयर पर चने की फसल है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि केवल उन किसानों की गेहूं, सरसों और चना खरीदी जाएगी, जिन्होंने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्-ट्रेशन कराया हो। इसके बाद दूसरे स्थानीय किसानों के बारे में सोचा जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों की रबी फसल यानी सरसों, गेहूं या चना नहीं खरीदेगी। फसलों में नमी आठ फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीएम ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में भी गेहूं व सरसो की खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि 5 दिनों में ही पूरी सरसों खरीदी जाएगी। सरसों का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में मिलेगा। गेहूं की अदायगी आढ़तियों के जरिए की जाएगी। गोदाम में फसल पहुंचते ही किसानों का पैसा रिलीज हो जाएगा।

सरकार का तर्क है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की अनिवार्यता से स्थानीय किसानों को अधिक मुनाफा होगा। दलालों के चुंगल से किसान बचेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि जब फसल ही नहीं बिकेगी तो फायदा किस बात का। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह श्योकंद कहते है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जटिल है। इसलिए किसानों ने दूरी बना रखी है। कभी सर्वर डाउन रहता है तो कभी जानकारी अपडेट नहीं होती है।

हेल्पिंग हैंड गायों को खिला रहा हरा चारा

संवाददाता रांची: हेल्पिंग हैंड गौ सेवा समिति के प्रवक्ता अमित चौधरी जानकारी दी की लॉकडाउन के वजह से जानवरों को भोजन के लिए जूझना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए कांके सुकुरहुट्टू गौशाला में गायों को 600 ताजा हरि सब्जियों को काट कर गायों को खिलाया गया है यह कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किया गया जोकि पिठौरिया से सब्जियां खरीद कर कांके सुकुरहुट्टू गौशाला में काट कर गौ माता को खिलाया गया।

सरकार के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यह कार्य हुआ हेल्पिंग हैंड महीने के दूसरे और चौथे रविवार को गौ सेवा करती है लेकिन इस लोग डाउन और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए हेल्पिंग हैंड ने चारों रवि-वार गौ सेवा करने का निश्चय किया है 5 अप्रैल को भी गौ सेवा की गई और आज 12 अप्रैल को भी गौसेवा की गई इस माह में आने वाले दोनों रविवार को भी गौ सेवा चालू रहेगी । अतः ऐसे में हमे इन बेजुबान जानवरो की मदद हेतु आगे आने की जरूरत है, ताकि इस विकट परिस्थितियों में हम सब उन्हें बचा सके। इस कार्य में मदद करने वालों में कन्हैया लाल भरतिया, अरुण बाजोरिया, नवीन वेरलिया,मनीष लोधा,और हेल्पिंग हैंड गोसेवा के सभी सदस्य गण हैं।

हटिया डैम से अब पानी की राशनिंग होगी

संवाददाता

हटिया डैम से 16 अप्रैल से शुरू होगी पानी की राशनिंग मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मिलेगा पानी मानसून तक रहेगी व्यवस्था, सभी पर्व त्योहारों में होगी जलापूर्ति

रांचीः झारखंड की राजधानी रांची के हटिया डैम से पानी की राशनिंग 16 अप्रैल से होगी। यह मानसून के आने तक जारी रहेगा। सोमवार और वृहस्पतिवार को जलापूर्ति बंद रहेगी। डैम का जलस्तर कम होने के कारण यह निर्णय लिया गया।

डैम में 10 फीट कम है पानी

अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2019 में हटिया डैम के आसपास के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश होने की वजह से यहां समुचित मात्रा में इतना पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे कि आगामी मानसून तक जलापूर्ति की जा सके। हटिया डैम में 2019 की तुलना में इस वर्ष लगभग 10 फीट पानी कम है। ऐसी परिस्थिति में हटिया डैम से जलापूर्ति क्षेत्रों में पानी का राशनिंग करना अति आवश्यक हो गया है। ऐसा करने पर ही आगामी मानसून तक समूचित मात्रा में उन क्षेत्रों में जलापूर्ति किया जा सकेगी।

बैठक में लिया गया निर्णय

रांची नगर निगम के नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 11 अप्रैल, 2020 को हुई बैठक में 16 अप्रैल, 2020 से पानी की राशनिंग करने का निर्णय लिया गया। हटिया डैम से जलापूर्ति होने वाले क्षेत्रों में सोमवार और वृहस्पतिवार को जलापूर्ति बंद रहेगी। मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को जलापूर्ति होगी। इस बीच सभी पर्व त्योहारों में भी सामान्य रूप से जलापूर्ति की जाएगी।

ये इलाके होंगे प्रभावित

प्रभावित क्षेत्रः एचईसी संपूर्ण आवासीय क्षेत्र एवं फैक्टरी परिसर, हटिया रेलवे स्टेशन, रांची एयरपोर्ट, हवाई नगर, बिरसा चौक से हिनू होते हुए दर्जी मुहल्ला तक सीधी जलापूर्ति क्षेत्र, हटिया स्टेशन रोड, बंधु नगर, प्रकाश नगर, गांधी नगर, शुक्ला कालोनी, किलबर्न जलापूर्ति क्षेत्र, दर्जी मुहल्ला जलागार से होने वाले जलापूर्ति क्षेत्र यथा दर्जी मुहल्ला एवं पारस कॉलनी और इसके संलग्न क्षेत्र। हिनू जलमीनार से जलापूर्ति होने वाले सभी क्षेत्र।

इन क्षेत्रों में कटौती नहीं

डोरंडा और नार्थ ऑफिस पाड़ा जलमीनार से जलापूर्ति क्षेत्रों, अशोक नगर और हरमु जलागारों से जलापूर्ति, अनंतपुर, निवारणपुर, रिसालदार नगर, नेपाल हाउस. 56 सेट क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में रूक्का जलशोधन संस्थान द्वारा हटिया लाईन के माध्यम से प्रतिदिन पानी मिलता है। इसके अनुसा जलापूर्ति होती रहेगी। जिसदिन रूक्का से हटिया लाईन में कोई बाधा उत्पन्न होगी, उन दिनों में उक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए न्यूनतम $ 200 बिलियन की जरूरत है : एसोचैम

एसोचैम अध्यक्ष डॉ निरंजन हीरानंदानी, ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक सिफारिश पत्र में, कोरोना महामारी के साथ अपनी लड़ाई के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई कड़े उपायों का प्रस्ताव दिया है।

एजेंसियां,नई दिल्ली: अभूतपूर्व समय से निपटने के लिए एक भावना के साथ, असाधारण उपाय आवश्यक हैं जिसके लिए एसोचैम ने 16 बिंदु एजेंडा और कम से कम $ 200- $ 300 बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की सिफारिश की है। दुनिया के इतिहास में सबसे गहरी वैश्विक मंदी की उम्मीद लगाई जा रही है, इसके महासचिव दीपक सूद कहते हैं कि चैंबर का मानना है कि दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 प्रतिशत के साथ प्रोत्साहन के उपायों को पूरा करने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर जाने के लिए 200 बिलियन डॉलर से अधिक के आधान की आवश्यकता होगी। और अगले 12-18 महीनों में $ 300 बिलियन से अधिक की जरुरत होगी । उन्होंने कहा कि कॉर्पस में से, 50-100 बिलियन डॉलर की नकदी को अगले तीन महीनों में सिस्टम में संचारित करने की जरूरत है, ताकि नौकरियों के नुकसान को रोका जा सके और आय की हानि की भरपाई की जा सके। इस तरह के व्यवसायों और श्रमिकों को चुनौतीपूर्ण स्थिति में काम करने में मदद करेंगे।

रेलवे करा रहा है जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन

रांची संवाददाता :वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए संपूर्ण देश में 21 दिन का लॉक डाउन किया गया है । कारणवश गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन तथा भोजन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। रांची रेल मंडल द्वारा प्रतिदिन गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

रांची रेल मंडल में सर्वो रांची मंडल, वाणिज्य विभाग, कार्मिक विभाग, रेल सुरक्षा बल, आईआरसीटीसी एवं भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा प्रतिदिन बड़ी तत्परता के साथ गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

13अप्रैल को रांची रेल मंडल द्वारा विभिन्न स्थानों पर 2180 गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया गया।

मंडल के वाणिज्य विभाग, कार्मिक विभाग एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा धुर्वा, बिरसा चौक में पेट्रोल पंप के नजदीक, हटिया रेलवे स्टेशन के पास,तथा बालसिरिंग एवं लोधमा स्टेशनों के बीच सोदाग गांव में लगभग 1580 लोगों को भोजन/भोजन सामग्री उपलब्ध कराया गया। वहीं सर्वो रांची मंडल, आईआरसीटीसी एवं भारत स्काउट एंड गाइड ने

बालसिरिंग, जोजोसिरिंग एवं तुपुदाना में 600 गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन उपलब्ध कराया गया।

मानसून से पहले की खरीफ फसलों की बुवाई शुरू

मुरलीधर

धान का रकबा 27 प्रतिशत बढ़ा

कोविड-19 वायरस प्रकोप के कारण लागू 'लॉकडाऊन' के बीच देश भर में मानसून से पहले खरीफ फसलों की बुवाई शुरू हो गई है। इसमें धान की खेती का रकबा पिछले सत्र की तुलना में 27 प्रतिशत बढ़कर 32.58 लाख हेक्टेयर हो गया। कृषि मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

बुवाई का काम, दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर) की शुरुआत के साथ गति पकड़ेगा। मानसून के दौरान देश की कुल वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत बारिश होती है।

खरीफ में दलहन और तिलहन के अलावा धान मुख्य खरीफ फसल होती हं

मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, किसानों ने शुक्रवार तक 32.58 लाख हेक्टेयर में धान बोया है, जो पिछले साल इसी अवधि के 23.81 लाख हेक्टेयर के रकबे से 27 प्रतिशत अधिक है।खरीफ मौसम जून से शुरू होता है और सितंबर माह में समाप्त होता है।

बुवाई का काम मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में 3.13 लाख हेक्टेयर, असम में 2.73 लाख हेक्टेयर, कर्नाटक में 1.64

लाख हेक्टेयर और छत्तीसगढ़ में 1.50 लाख हेक्टेयर रकबे में हुआ है।

मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु में बुवाई का रकबा 1.30 लाख हेक्टेयर है जबकि बिहार में 1.22 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 0.65 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 0.59 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 0.54 लाख हेक्टेयर और केरल में 0.46 लाख हेक्टेयर हैं। समीक्षाधीन अवधि में दलहन बुवाई का रकबा बढ़कर पहले के 3.01 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 3.97 लाख हेक्टेयर हो गया। इसमें से, 2.59 लाख हेक्टेयर में हरा चना और 1.23 लाख हेक्टेयर में कालाचना बोया गया है और 0.15 लाख हेक्टेयर में अन्य दलहनी फसलें लगाई गई हैं।

इसी तरह, मोटे अनाजों का रकबा एक साल पहले 4.33 लाख हेक्टेयर के मुकाबले इस साल के चालू खरीफ सत्र में अब तक 5.54 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। इसमें से 2.81 लाख हेक्टेयर में मक्का और 2.51 लाख हेक्टेयर में बाजरे की बुवाई की गई है। तिलहन मामले में भी, समीक्षाधीन अवधि में बुवाई का रकबा पहले के 5.97 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 6.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें से मूंगफली 4.08 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जबकि 2.13 लाख हेक्टेयर में तिल की बुवाई हुई है।

सभी खरीफ फसलों के तहत खेती का कुल रकबा इस वर्ष अब तक बढ़कर 48.76 लाख हेक्टेयर हो गया है जो रकबा पिछले साल 37.12 लाख हेक्टेयर था।

कोविड-19 की रोकथाम के लिए, सरकार ने किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई के समय किसी भी संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के अलावा बुवाई के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। इस बीच, सरकार ने 16 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया है, जिसमें धान जैसी खरीफ फसलों की बुवाई के लिए एक रणनीति तैयार की जायेगी तथा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विचार किया जायेगा।

संथाल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स जानवरों को भोजन करायेगा

देवघर संवाददाता:उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस से बचाव हेतु किये गए लॉक डाउन के वजह से मनुष्य से लेकर जानवरों तक को भोजन के लिए जूझना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए संथाल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा गौ-सेवा के तहत बेजुबान जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया गया है। इसके तहत इनके द्वारा सड़कों पर घुमने वाले गाय, बैल, सांढ़, आदि पशुओं को भोजन कराया जाएगा एवं शहर के बैद्यनाथपुर, बेलाबगान, बिलासी, ठाढ़ीदूलमपुर एवं बाबा मंदिर के आस-पास के चालीस स्थानों को चिन्हित किया गया है तथा प्रतिदिन इन स्थानों पर गाय, बैल, भैंस, बछड़ा आदि के लिए भोजन स्वरुप चोकर, नारा, कुट्टी आदि की आपूर्ति की जाएगी। साथ हीं पानी और साफ़ सफ़ाई से संबंधित अन्य व्यवस्थायें भी की जाएगी।उपायुक्त ने कहा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स का यह पहल सराहनीय है एवं विपदा की इस घड़ी में जिस प्रकार देवघरवासी एवं विभिन्न संस्थाएं आगे आकर बेजुबान जानवरों को भोजन कराने का कार्य कर रहे हैं, वह वास्तव में सराहनीय है। नैन्सी सहाय ने कहा कि बेजुवानों के प्रति प्रेम भाव हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इनके प्रति सभी लोग संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण पेश करें।

उपायुक्त ने सभी जिलावासियों से आग्रह किया कि गर्मी को देखते हुए लोग अपने घरों के छतों पर पंरिदों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था जरूर करें एवं लॉक डाउन के दरम्यान बेजुबान जानवरों के सुविधा हेतु घर के आस-पास या दरवाजे के समीप भोजन या पीने के पाना की व्यवस्था कर अन्य लोगों को भी ऐसा करने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि हम सभी को कहीं न कहीं भोजन मिल जा रहा है पर बेजुबान भूखे रह जा रहे है। ऐसे में हमे इन बेजुबान जानवरो की मदद हेतु आगे आने की जरूरत है, ताकि इस विकट परिस्थितियों में हम उन्हें बचा सके।

एशिया की सबसे बड़ी मंडी में 50 फीसदी गिरावट

एजेंसियां :लॉकडाउन के बाद से आवक में करीब 50 फीसदी की गिरावट आई है। सप्लाई चेन टूटने के बाद से किसानों का माल सामान्य दिनों की तरह आजादपुर मंडी नहीं पहुंच रहा है।

लॉकडाउन से पहले आजादपुर मंडी में 20 मार्च, 2020 को जहां 1912 वाहन, वहीं 2240 वाहन वितरण के लिए पहुंचे थे। 26 मार्च को सिर्फ 881 वाहन आए और वितरण वाले वाहनों की संख्या 1315 पहुंच गई। 27 मार्च को रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक 293 वाहन आए और करीब एक हजार वितरण वाले खाली वाहन आए।लॉकडाउन के बाद आजादपुर मंडी पहुंचने वाले इन ट्रकों में सबसे ज्यादा माल आलू, टमाटर और बैंगन का है। हालांकि, आलू की कीमतों में आवक के बाद भी बढ़ोतरी है। आलू की कीमत 600 से 800 रुपये के बीच बिका था लेकिन 27 मार्च, 2020 को आलू की कीमत 1100-2000 रुपये तक रही। मिर्च की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुंच गई है।

फोटो न्यूज

हरे भरे घुमने लायक जगह को ठेकेदारों ने बर्बाद कर दिया है: तस्वीर कांके डैम के किनारे सरोवर नगर इलाके की है जहां ग्रीनलैंड के मैदान में नाले को ढकने के लिये ठेकेदारों ने सैकड़ो स्लैब ढाल कर रख दिये और सब कुछ वैसे ही छोड़ कर चले गये। अब जो जगह खेलने घूमने की थी वहां ये कंक्रीट के स्लैब बिखड़े पड़े हैं?

अच्छी नींद मानव जीवन के लिए वरदान

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

एक बहुत ही पुरानी कहावत है .... " sleep like a baby" जिसका मतलब है आपकी नींद एक छोटे बच्चे के जैसी होनी चाहिए। अच्छी नींद मानव जीवन के लिए वरदान से कम नहीं है। नींद उतनी ही आवश्यक है जितना की भोजन ,जल और कसरत। मानव शरीर भी एक मशीन की तरह ही काम करता है और मशीन की तरह इसे भी मेनटेनेंस की जरूरत होती है।आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से नींद कम हो गई है। डॉक्टर के मुताबिक स्वस्थ रहने के लिए किसी भी इंसान को 6-8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है । आज हम नींद में कमी के कारण और उसके उपाय के बारे में बात करेंगे।

नींद में कमी के कारण

स्मार्ट गैजेट्स- स्मार्ट गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन से निकलने वाली कृत्रिम रोशनी आंखो की पुतलियों के लिए काफी हानिकारक हो सकती है । ये रोशनी हमारे दिमाग को कृत्रिम तरीके से सक्रिय करती है जिसके कारण सोने जागने का समय चक्र बदल जाता है और इसका दुष्परिणाम हमारी सेहत पर दिखता है।

लेट नाईट ड्यूटी -कुछ लोगों का काम ऐसा होता है जिसमें उन्हें 24X7 सक्रिय हो होना पड़ता है और काफी देर तक रात तक काम भी करना पड़ता है जिससे स्लिप पैटर्न डिस्टर्ब होता है।

मानसिक तनाव/डिप्रेशन

आज कल के युग में लोगों का मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि लोगों में नकारात्मक सोच चिंता और बिना कारण का मन में डर बढ़ गया हैं। जिसके कारण हमें मानसिक तनाव रहता है और ये हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को डिस्टर्ब करता है और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है जिसके कारण नींद की समस्या होती है।

बढ़ती उम्र

बढ़ती उम्र से शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं जिससे नींद कम हो जाती है।अल्कोहल/चाय/काफी का सेवन- अल्कोहल या चाय /काफी का सेवन मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है और ये नींद में बांधा लाती है। सोने से पहले इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।

अच्छी नींद के लिए कुछ उपाय

सोने और उठने का समय निर्धारित करें- अपने सोने और उठने का समय निर्धारित करना चाहिए जिससे आपके सोने और जागने का चक्र निर्धारित हो जाता है और धीरे -धीरे आप समय पर और गहरी नींद में सोने लगते हैं।

आरामदायक बेड चुनें

बेडरूम साफ -सुथरा , हवादार और आरामदायक होना चाहिए। जहां हम सोते हैं वहां शोरगुल भी नहीं होना चाहिए। हाथ पैर धोकर और तेल मालिश कर के सोना चाहिए- सोने से पहले हाथ पैर धोकर या गुनगुने पानी से नहाकर सोने से अच्छी नींद आती है । गुनगुने तेल से तलवे पर या सर पे मालिश करने से भी अच्छी नींद आती है।

व्यायाम करें

व्यायाम करने से शरीर से अच्छे हारमोन्स रिलीज़ होते हैं जिससे आप रिलैक्स महसूस करते हैं और समय पर नींद आती है । कसरत करने से शरीर चुस्त और मन शांत होता है।

प्राणायाम करें

अगर नींद नहीं आने की ज्यादा समस्या हो तो सुबह उठकर और रात को सोने से पहले प्राणायाम का अभ्यास करें। अनुलोम-विलोम और भ्रामरी या सिर्फ डीप ब्रीदिंग करें।

एक खास बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सोने से पहले और बेडरूम में जाने से पहले अपने चिंता रूपी कवच को बाहर ही छोड़ देना चाहिए ठीक वैसे ही जैसे आप अपने जुते दरवाजे के बाहर निकालते हैं। हमेशा खुश रहे ,खान -पान अच्छा रखें, चिंता मुक्त रहें । इन सब बदलाव से आपके नींद न आने की समस्या में सुधार होने लगेगा।

महुआ, टोकरी, इमली नहीं बिक रहे

एजेंसियां : देशभर में लॉकडाउन का असर सभी लोगों पर तो हुआ ही है लेकिन हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग है जो पहले से हाशिये पर है उनके आजीविका पर इसका असर दिखाई देने लगा है। बांस की टोकरी आदि बनाना बहुत सारी जनजातियों की पारंपरिक आजीविका का साधन है। जिसे बाहर से व्यापारी लोग आते हैं और यह सामान खरीदकर ले जाते हैं। यह महुआ का भी समय है, आजकल लोग महुआ फूल बीनने जंगल जा रहे हैं, लेकिन बाजार बंद है, इसलिए महुआ भी नहीं बिक रहा। आदिवासी जनजातियों की आजीविका का महुआसबसे बड़ा साधन है । इस लॉकडाउन ने इमली, महुआ जैसी सभी वनोत्पादों का बाजार भी लॉक कर दिया है। इस कारण ने आदिवासियों की कमाई का मुख्य जरिया भी बंद हो गया है।

यूरोप में कोरोना से नहीं बिक रहे गुच्छी मशरूम

एजेंसियां : कोरोनावायरस का यूरोपीय देशों पर व्यापक असर हुआ है। 12 अप्रैल तक करीब 9 लाख कोरोना पॉजीटिव केस सामने आए हैं। 75 हजार लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन यह तत्कालिक असर है। निकट भविष्य में आर्थिक दुश्वारियां आनी बाकी हैं। यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना के असर का आकलन अभी जारी है, लेकिन इस झटके की आहट हजारों मील दूर हिमालय के दूर-दराज गांवों तक महसूस की जाने लगी है। दरअसल, भारतीय बाजार में 10-12 हजार रुपए प्रति किलो की कीमत वाली गुच्छी, यूरोप के मार्किट में पहुंचने तक 35 हजार तक की हो जाती है। पहाड़ी लोग जंगलों से गुच्छी चुनते हैं क्योंकि, इसकी खेती नहीं होती। इसलिए बेतहाशा मांग के बावजूद पार्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती। इससे गुच्छी बेचने वालों का ही फायदा होता है और कभी दाम गिरते नहीं हैं।

पहाड़ के लोगों ने लिए ये आमदनी का स्थायी जरिया है। गुच्छी तीन महीने की फसल है। अप्रैल, मई और जून। तीन महीने में ठीक-ठाक माल इकट्ठा हो जाता है। 10 हजार प्रति किलो तक रेट मिल जाता है। पर इस बार अमृतसर मंडी में इसका रेट 3-4 हजार रू प्रति किलो है करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बसे चंबा जिले के भरमौर कस्बे में लोगों की आमदनी का बड़ा हिस्सा जड़ी-बूटियों से आता है। बर्फबारी के दौरान 4 महीने तक पूरी दुनिया से कट जाने वाले इन ठंडे इलाकों सबसे कीमती जड़ी-बूटियां मिलती हैं। कुछ जंगली, तो कुछ की खेती होती है। गुच्छी का दाम अच्छा मिलता है। नागछतरी, कुटकी, पतीश,

सालम पंजा जैसी जड़ी-बूटियां इस इलाके में लोग ज्यादा उगाते हैं। और कारोबार में घाटा हो भी, तो गुच्छी से ही पूरा होता जाता है, लेकिन अब इस लॉकडाउन से लोग डरे हुये हैं। हिमाचल में किसानों और बागवानों के लिए प्राकृतिक नुकसान की भरपाई के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन जड़ी-बूटियों के कारोबारियों और किसानों के लिए सीधे तौर पर कोई योजना नहीं है।

लोग जंगल से माल ला रहे हैं। घरों में पड़ा है, लेकिन खरीदने को कोई तैयार नहीं। किसानों के पास माल रखे हुये हैं लेकिन इन हालात में कोई व्यापारी माल खरीदने से डर रहा है।

एकल परिवार सोशल डिस्टेंसिंग में है बाधक

देवाशीष

रांची :शहरों में हमारे घरों की बनावट सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अनुकूल नहीं है, और लगातार घर में बने रहने से मानसिक तनाव व झल्लाहट हो सकती है। ऐसे में यदि आपके घर में 'ग्रीन एरिया' हो तो वहां समय बिताया जा सकता है, पेड़ों के आस-पास समय बिताने से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। और यदि ऐसी जगह न है, तो सुबह-शाम छतों पर जाएं। आजकल प्रदूषण कम होने से आसमान साफ है, उसे निहारें। इससे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

यह अवधि एक अवसर की तरह है, उन सभी चीजों को करने का, जो अक्सर भाग-दौड़ भरी जिंदगी में छूट जाती है। संपर्क साधनों के आने से हमारा सामाजिक संपर्क बढ़ने के बावजूद 'म्यूच्यूअल डिस्टेंसिंग' (आपसी दूरी) भी बढ़ी है। हमें इस सोशल डिस्टेंसिंग पीरियड में 'म्यूच्यूअल कनेक्टिविटी' पर जोर देना है।

इस पीरियड में अपनी दिनचर्या को बेहतर करने पर जोर दें। सूर्योदय व सूर्यास्त को देखें, जिससे कि बड़ी आबादी वंचित है। ध्यान व योगाभ्यास करें। अपनी कलात्मकता को उभारें, जैसे डांस, संगीत, कुकिंग आदि। और वह सब कुछ, जो आप करना चाहते हैं, लेकिन समयाभाव में नहीं कर पाते।

यह आंतरिक यात्रा का समय है

रश्मि सुमन

देशभर में लॉकडाउन लागू है और डॉक्टरों की ओर से कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी कायम रखने की सलाह दी गई है। सामाजिकता व सह-अस्तित्व का उत्सव मनाने वाले मानव के लिए एकांत व सामाजिक दूरी थोड़ी अव्यावहारिक जरूर है। वहीं सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), आइसोलेशन, व एकांत (क्वारंटीन) जब चुनी जाती है, तो हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होते हैं।

साथ ही इस दौरान दिनचर्या के बदलावों को लेकर भी हम खुद को तैयार कर लेते हैं। वहीं जब यह आरोपित होती है, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। यह अस्वीकार्यता ही बेचैनी (एंजायटी) का कारण बनती है, जो आगे डिप्रेशन में बदल जाती है। यदि हम इसे स्वीकार लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम सब एक ब्रेक चाहते हैं। इसलिए इसे वह ब्रेक ही मानें। हालांकि जब हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते, तो इससे कई तरह की दिक्कतें होती हैं। आज के समय में एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है, यह पारिवारिक संरचना आइसोलेशन व क्वारंटीन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता रहता है, बेचैनी व डिप्रेशन की संभावना कम रहती है। क्योंकि जब हम अपनी भावनाओं को कह पाते हैं, तो इससे मानसिक दबाव कम हो जाता है। और ऐसा न हो पाने की स्थिति में कुंठा की स्थिति बन जाती है। इसका विशेष खयाल रखने की जरूरत है।

छोटे परिवारों में अक्सर माता-पिता नौकरी पेशा होते हैं। और बच्चों को कई चीजों के बारे में अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत होती है। इसलिए इस लॉक-डाउन का असर बच्चों व अधिक उम्र के लोगों पर होने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में मां-बाप को इसका ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को अधिक से अधिक समय देकर उन्हें रचनात्मक कामों में लगाना चाहिए। बच्चों पर झल्लाएं नहीं, बल्कि उन्हें प्यार से समझाएं। अपने अब तक के जीवन को देखें, और उसकी समीक्षा करें। पुराने एल्बम देखें, और उससे जुड़ी यादों की चर्चा करें। परिवार के साथ चेस, कैरम व लूडो आदि सामूहिक खेल खेलें। परिवार के साथ अपनी भावनाएं साझा करें। आपस में अधिक जुड़ाव बनाने की कोशिश करें। खाना मिलजुल पकाएं व घर की साफ सफाई करने में एक दूसरे की मदद करें, इसे देखकर बच्चों में भी आपसी सहयोग की भावना विकसित होगी। पुस्तकें पढ़ें, व डायरी लिखें। जो अकेले रहते हैं, वे ध्यान जरूर करें। यदि आप गाते हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग करें, फिर सुनें और ठीक करें।

(लेखिका मनोवैज्ञानिक सलाहकार हैं।)

कहां गईं रंग बिरंगी वो तितलियां

प्रयाग शुक्ल

तितलियों पर बहुत-सी चीजें लिखी गई हैं। कविताएं और गीत भी बहुतेरे हैं। 'पंछी बनूं उड़ती फिरूं' गीत की याद बहुतेरे लोगों को होगी। उसी की तर्ज पर 'तितली बनूं उड़ती फिरूं' भी कह सकते हैं। बच्चों के लिए लिखने वाले कवियों की भी कविताएं हैं तितली पर। वह रूपक और प्रतीक भी बनती रही है। और एक छवि, एक बिंब के रूप में भी वह अनुपम है।

आपने हाल में क्या कहीं कोई तितली देखी है? यह सवाल मानो मैं अपने से भी कर रहा हूं। नोएडा में जहां मैं रहता हूं, वहां खूब पेड़-पौधे हो गए हैं। फूलों की क्यारियां और उनके गमले भी हैं। परिसर में घास भी है। पर तितलियां कम दिखती हैं। जब दिखती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई तितली थोड़ी देर के लिए कहीं आसपास बैठी हुई मिल जाए तो उसकी ओर ही देखता रहता हूं। एक बार मोबाइल के कैमरे से उसकी तस्वीर खींचने में भी सफल हो गया था। तितली घास पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैं यह 'चुपचाप' क्यों लिख गया! यह तो अतिरिक्त शब्द माना जाएगा! तितली तो बेआवाज ही उड़ती है, बेआवाज ही बैठती है, पंख खोलती है तो कोई फड़फड़ाहट भी सुनाई नहीं पड़ती। यही तो उसकी खूबी है- कई खूबियों के बीच। वह किसी भी रंग की हो, हमेशा सुंदर ही लगती है। पर अफसोस, उसकी कुछ प्रजातियां खोती या कम होती जा रही हैं- दुनिया भर में। कई देशों में उसके पोसने के जतन भी किए जा रहे हैं। कुछ बरस पहले जब लंदन में 'गार्डियन' जैसे पत्र में एक सचित्र लंबी रिपोर्ट पढ़ने को मिली थी कि किस प्रकार विभिन्न पार्कों या उद्यानों में यह तलाश की जा रही है कि वहां कितने प्रकार की तितलियां अब देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तितली पर बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। कविताएं और गीत भी बहुतेरे हैं। 'पंछी बनूं उड़ती फिरूं' गीत की याद बहुतेरे लोगों को होगी। उसी की तर्ज पर 'तितली बनूं उड़ती फिरूं' भी कह सकते हैं। बच्चों के लिए लिखने वाले कवियों की भी कविताएं हैं तितली पर। वह रूपक और प्रतीक भी बनती रही है। और एक छवि, एक बिंब के रूप में भी वह अनुपम है। रूस के प्रवासी लेखक ब्लादिमीर नोबोकोव की तो तितली पर एक किताब ही है। जो भी हो, उसकी लोकप्रियता सबके बीच है।

बीती सर्दियों में मैं अपने रिहायशी परिसर के पार्क में घास पर कुर्सी डाल कर कई बार बैठा धूप सेंकने या लिखने-पढ़ने के लिए। जब भी तितली दिखी है- कभी कभार या एक-दो दिनों के अंतराल पर दिखी। मैंने कुछ चकित-विस्मित होकर ही उसकी ओर देखा। हां, अब स्वाभाविक रूप से वह विस्मित करती है, जब बहुत कम दिखाई पड़ती है। मैं समझता हूं, नोएडा-दिल्ली समेत अब बहुतेरे महानगरों-शहरों का यही हाल हो गया है, तितलियों के मामले में। प्रकृति की, सृष्टि की इतनी सारी चीजें कम हो रही हैं, यह चिंताजनक तो है ही। भौंरे भी कम दिखने लगे हैं। खैर, सोचिए कि पिछली बार कोई तितली आपने कब और कहां देखी थी! शायद उसके साथ आपको वह जगह भी याद आ जाए, जहां आपने उसे देखा था। इसका कारण भी यही होगा कि वह अब कुछ दुर्लभ हो गई है। कोई दुर्लभ हो चुकी चीज अगर दिख जाए तो उसे दिखने के स्थान-काल सब याद रह जाते हैं। दो तीन बरस पहले की बात है, मैं और मेरी नातिन कार से कहीं जा रहे थे। चिराग दिल्ली पंचशील क्रॉसिंग की ट्राफिक लाइट में गाड़ियां रुकीं तो हमें बाहर उड़ती हुई एक तितली नजर आई। हम कुछ देर तक उसे देखते रहे।लोगों और वाहनों की भीड़ में यही सोचते हुए कि वह यहां कैसे आ गई है भटक कर! वह कहीं भी दिखे भीड़ भरी जगह में, किसी फूल-पौधे पर, किसी रेलिंग-फेंस पर, किसी पार्क में- अपनी ओर ध्यान खींच लेती है। हम उसे देखने लगते हैं। जब वह फूल पर बैठती है तो दोनों की मिली-जुली सुंदरता दोगुना नहीं, कई गुना बढ़ जाती है। तितलियां आमतौर पर हर महाद्वीप में पाई जाती हैं। मुझे वह जमाना याद है, जब तितलियां बाग-बगीचों में उड़ती रहती थीं। और इस तरह के प्रश्न का तो मौका ही नहीं आता था कि आपने पिछली बार तितली कब देखी थी!

तितली की एक बड़ी खासियत यही है कि अगर आप दुख का कोई भार साथ में लिए हुए चल रहे हों और तभी तितली दिख जाए तो क्षण भर के लिए तो वह उस भारी भार को उतार ही देती है आपके मन से। अगर आप किसी सुख, किसी आनंद, को साथ में लिए चल रहे हों, तो वह आपको और अधिक आनंदित कर देती है। वह उड़ती है। मुड़ती है। ओझल हो जाती है। फिर दिखती है।

हवा में उसका संतरण अचूक है। उसकी उड़न-गति प्रभावित करती है। अनायास आपकी आंखों को अपनी ओर बुला लेती है। वह बोलती नहीं है, पर बिना बोले हुए भी बहुत कुछ कहती है। वह भारहीन लगती है। सचमुच भारहीन है भी। उसकी यही भारहीनता मोहती है। अपनी सुंदरता को वह जिस भारहीन ढंग से हमारे भीतर उतारती है, उसे कह कर नहीं बताया जा सकता, वह महसूस किया जा सकता है। फुलवारियां, क्यारियां उन्हें लुभाती हैं। दिखती रहें तितलियां। बहुमंजिली इमारतों और सीमेंट-कंक्रीटी जंगल से भी ओझल न हो जाएं।

E ZONE CARE

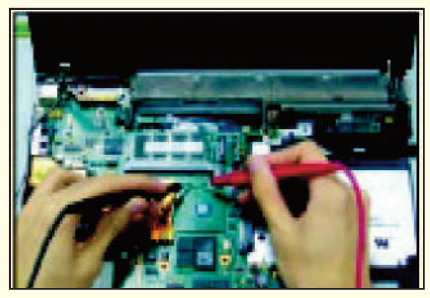

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।